Cn $ 200,000 from the International Centre for sustainable cities and US $ 80,000 from UNCHS will inter-alia document the project experience and explore the possibilities of replicating the project concept in other cities.

निदेशक (कमर्शियल), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में विचार

752. **श्री जनार्दन यादव:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जून, 1995 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कमर्शियल), श्री दास पटनायक ने अपनी जन्म तिथि के वर्ष को 1931 के स्थान पर 1937 बनाकर "सेल" के साथ धोखा किया है;

(ख) क्या श्री दास पटनायक सेल में कार्य करते आ रहे हैं जबकि उन्हें छः वर्ष पूर्व सेवानिवृत हो जाना चाहिए था;

(ग) क्या उन्होंने छः वर्षों की इस अनैध सेवा-अवधि के दौरान कोई गलत आदेश जारी किए हैं; और

(घ) क्या सरकार श्री दास पटनायक पर जालसाजी करने का मुकदमा चलाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सन्तोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने इस्पात मंत्रालय को सूचित किया है कि श्री एस०के० दास पटनायक की वैयक्तिक फाइल में उल्लिखित सूचना के अनुसार उन्हें 31.8.1995 से सेवा-निवृत होना था। तथापि, उन्होंने अपना त्याग-पत्र इस आधार पर दिया था कि वे "सेरिबेरल अटैक" से बीमार हैं, और उसके बाद उनका स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा था। इसे स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार 13-7-1995 (अपराह्न) से उन्हें से उन्हें "सेल" की सेवा से मुक्त कर दिया गया।

(ग) "सेल" के अनुसार श्री एस० के० दास पटनायक ने अपनी पिछली 6 वर्ष की सेवा के दौरान न तो कोई गलत आदेश जारी किया और न ही कोई गलत निर्णय लिया।

(घ) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए श्री एस०के० दास पटनायक के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए फिलहाल इस्पात मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Expensive Books printed by NCERT

753. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Council for Educational Research and Training (NCERT) has printed expensive text books much against the spirit of the National Education Policy;

(b) if so, the reasons therefor and whether any action has been taken/likely to be taken by Government against the officials responsible for expensive printing of NCERT text books; and

(c) if so, the details thereof and if not the reasons therefor stating its impact on aims of National Education Policy to provide cheap reading material to all School Children in the Country?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) (a) to (c) the National Policy on Education (NPE), 1986, envisages making efforts to secure easy accessibility to books for all segments of people and for special attention to be paid to the production of quality books for childern.

The NCERT continues to provide cheap textbooks and the sale prices of its textbooks are determined as per the approved pricing formula based on no-profit-no-loss.